रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062023-246283
CG-DL-E-05062023-246283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2322] नई दिल्ली, सोमवार, जून 5, 2023/ज्येष्ठ 15, 1945
No. 2322] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 5, 2023/JYAISHTHA 15, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2023

का.आ. 2432(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 2 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5880(अ), तारीख 15 दिसंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार, तारीख 15 दिसंबर, 2022 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का छह मास की और अवधि के लिए विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंककारी उद्योग में लगी हुई सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जून, 2023 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/5/97-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2023

S.O. 2432(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 15th December, 2022 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 5880 (E), dated 15th December, 2022;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 15th June, 2023**.**

[F. No. S-11017/5/ 97- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.06.05 22:55:27 +05'30'